प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

20.05.2025 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

प्रतिनिधिमंडल

तुर्कीए के सेब आयात को बंद करने की मांग प्रदेश में लगातार ज़ोर पकड़ रही है। शिमला ज़िला के कोटखाई क्षेत्र के थरौंक के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर तुर्किए के सेब आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का मुद्दा केन्द्र सरकार की समक्ष उठाने सहित अन्य मांगे भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया।

किसान मंच

इस बीच हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तुर्किए के सेब आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर एक ज्ञापन भेजा है। किसान मंच के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि तुर्कीए के सेब आयात होने से हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू–कश्मीर के बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्कीए से सेब आयात पर केन्द्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए।

तर्की जो है एक ऐसा देश है जिससे भारत में सबसे ज़्यादा सेब आयात होता है। 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ की आर्थिकी की सेब की वो भारत से लेता है। यानि भारत में सेब निर्यात कर हमारा पैसा दुश्मन देश की मदद के लिए लेता है। और आज जो हम महामहिम राज्यपाल महोदय को मिले हैं हमने महामहिम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन भेजा है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा है की तत्काल प्रभाव से दुश्मन देश के साथी दुश्मन देश का सारा आयात निर्यात तत्काल बंद कर दिया जाए। जिसमे की हम हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को भी सेब के रूप में निश्चित रूप से फायदा होगा।

तिरंगा यात्रा

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के जवानों के शौर्य के सम्मान में शिमला बार एसोसिएशन द्वारा आज कोर्ट परिसर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने भारतीय सेना के पराक्रम, बलिदान और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम सैनिकों के सम्मान और गौरव को समाज के हर स्तर तक पहुंचाए। सुरेश कश्यप ने शिमला बार एसोसिएशन की इस पहल को अत्यंत प्रेरणादायक बताया।

दृष्टिहीन संघ

बैकलॉग कोटे की भर्तियों की मांग को लेकर एक बार फिर से दृष्टिहीन संघ ने शिमला में राज्य सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गई। दृष्टिहीन संघ को शिमला में आंदोलन करते हुए 5 सौ 81 दिन हो गए हैं लेकिन सरकार इनकी मांगो को अनदेखा कर रही है जिसके चलते दृष्टिबाधित संघ बार बार सचिवालय के बाहर चक्का जाम कर रहा है। संघ के सदस्य लक्की ने बताया कि बैक लॉग कोटे की भर्तियां लंबे समय में लटकी है। सरकार से कई दौर की वार्ता के बाद भी परिणाम सकारात्मक नहीं आए जिसके चलते मजबूरजन चक्का जाम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी हर बार आश्वासन दिया लेकिन भर्तियां नहीं हुई और न ही

पेंशन बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार जबतक बैक लॉग कोटे की भर्तियों को नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

581 दिन से हम दिन रात परेशान हो रहे हैं, कई तरह की प्रॉबलमों का हमें सामना करना पड़ रहा हैं। लेकिन सरकार हमें हमेशा कभी 15 दिन का समय देती है, कभी 1 महीने का समय देती है, कभी 2 महीने का समय देती है। इस बार हम किसी भी अधिकारी से अंदर जाकर वार्तालाप नहीं करेंगे । मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुखु जी, अगर खुद हमें अंदर मीटिंग के लिए बुलाते हैं और सीए साहब को साथ मौजूद रखते हैं तभी हम मीटिंग के लिए जाएंगे । उन्होंने हमसे हमेशा झूठे वादे किए है और झूठी तारीख दी है। आज से पहले जितनी भी मीटिंगे हुई, वो सिर्फ निरंतर हमारे अंदोलन को हटाने के लिए की गई है।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि हिमाचल की विशिष्ट संस्कृति यहां की उच्च परम्पराओं में निहित है और हमारी परम्पराएं जन–जन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का संदेश देती है। उन्होंने आज सोलन में आगामी 20 जून से 22 जून तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय माता शूलिनी मेले के आयोजन के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। शांडिल ने ज़िला प्रशासन को मेले में तहबाजारी के लिए आने वाले व्यापारियों का पंजीकरण करने के निर्देश भी दिए।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 मई रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 122वां संस्करण होगा। इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल–फ्री नंबर 1800–11–7800 के माध्यम से भेज सकते हैं। लोग अपने सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप या माईगोव ओपन फोरम के जरिए भी साझा कर सकते हैं। ये सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे।